भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

7 जून 2011

बस्तरिया जनता की जिंदगी को पटरी से उतारने वाली रावघाट रेल लाइन व खदान परियोजना का विरोध करो!

भिलाई स्टील प्लांट को बचाना एक बहाना है!

बस्तर की संपदाओं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बेचने पर ही निशाना है!!

एक तरफ बस्तर में सेना की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो ही रही थी, दूसरी तरफ स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया (सेल) ने यह घोषणा की कि रावघाट खदानों का निजीकरण किया जाएगा। ये दोनों काम एक साथ इत्तेफाक से नहीं, बल्कि एक षड्यंत्रपूर्ण तालमेल से हो रहे हैं। बस्तर के जिस नारायणपुर जिले (माड़ क्षेत्र) में सेना की प्रशिक्षण स्कूल के लिए 750 वर्ग किलोमीटर (यानी 1,85,250 एकड़ से कुछ ज्यादा) जमीन सौम्पने को रमनसिंह सरकार ने सहमति दे दी, उस नारायणपुर से महज 25 किलोमीटर दूर पर स्थित रावघाट पहाड़ों में निक्षिप्त उच्चकोटी का लौह खनिज अब नामी-गिरामी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौम्प दिया जाएगा। एक तरफ सेना और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट कम्पनियां समूचे माड़ इलाके को निगलने जा रही हैं जो प्राचीन मानव समुदायों में से एक - माड़िया व गोण्ड आदिवासियों का निवास स्थल है।

2006 में, रावघाट परियोजना पर काम शुरू करने से पहले ही भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन पर यह आरोप लगा था कि उसने रावघाट की डिपाजिटें टाटा और निको कम्पनियों को चुपके से पट्टे पर दे रखी थीं। लोगों को साफ लग रहा था कि बीएसपी प्रबंधन टाटा, एस्सार, जिंदल, निको जैसे बड़े पूंजीपति घरानों के हाथों में मोहरा बन चुका है। लेकिन बाद में उसने बड़ी चतुराई के साथ लीपापोती कर जैसे-तैसे मामले को सुलटा लिया। लेकिन अभी-अभी स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया (सेल) के चेयरमैन चंद्रशेखर वर्मा ने खुद ही यह संकेत दे दिया है कि रावघाट का निजीकरण होगा और इसके लिए ग्लोबल टेंडर बुलाए जाएंगे। (स्रोत : दैनिक भास्कर, 24 मई 2011)। इसके साथ ही लुकाछुपी का खेल समाप्त हो जाता है! शोषक सरकारों का इरादा साफ है। देश में लागू नव-उदार नीतियों के तहत क्या रावघाट, क्या भिलाई स्टील प्लांट, पूरे सेल को ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां निगल सकती हैं। देश के दूसरे इलाकों में पोस्को, वेदांता जैसे ताजा उदाहरण भी यही समझा रहे हैं।

बताया जाता है कि रावघाट पहाडों में कुल 740 करोड़ टन लौह खनिज मौजूद है जोकि 62 प्रतिशत एफई ग्रेड का - सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है। यहां पर भिलाई स्टील प्लांट (सेल की इकाई) द्वारा 511 मिलियन टन का उत्खनन करना प्रस्तावित है। इसके लिए दल्ली-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण-कार्य जारी है। इसके तहत सरकार ने दल्ली से रावघाट तक किसानों से जमीनों को जबरन हड़पने का काम शुरू किया जिसका स्थानीय जनता पुरजोर विरोध कर रही है।

यह योजना दरअसल काफी पुरानी है। 1992 में लोगों के जबर्दस्त विरोध के कारण इसे रोक दिया गया था। अंतागढ़ के पास उस समय 10 हजार आदिवासियों ने एक विशाल रैली निकाल कर प्रस्तावित खदान परियोजना का जोरदार विरोध किया था। सहज ही, सरकार ने इसका जवाब दमन से ही दिया था जैसा कि वह हमेशा करती है। इन पहाड़ों पर एक पुलिस छावनी भी खोल दी गई जो आज भी मौजूद है। जनता के इस जायज संघर्ष का हमारी पार्टी शुरू से सक्रिय समर्थन देती आ रही है।

स्थानीय जनता की आपत्ति यह है कि इन पहाड़ों में खदान शुरू करने से 3,278 हेक्टेयर जंगल का पूर्ण विनाश होगा। इसके अलावा भी आसपास के जंगलों का भी भारी नुकसान होगा। इस क्षेत्र से होकर बहने वाली मेंढ़की, आदि कई नदी-नाले प्रदूषित हो जाएंगे। इससे खेती-किसानी का कितना भारी नुकसान होगा इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। इन पहाड़ों को स्थानीय लोग अपनी आस्था का केन्द्र और सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं जो इस खदान के खुलने के बाद हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कई पर्यावरणविद् मानते हैं कि बस्तर के पर्यावरण और मानसून के नजरिए से भी रावघाट पर्वतशृंखला बेहद महत्वपूर्ण है। रावघाट खदान परियोजना के कारण तत्काल 23 गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा, बगल में स्थित चारगांव के पास एक निजी कम्पनी निको जयस्वाल द्वारा प्रस्तावित खदान के चलते चारगांव के अलावा 13 अन्य गांवों के आदिवासियों की जिंदगी अस्तव्यस्त होने वाली है। (और इसमें जोड़ लीजिए अभी सेना द्वारा प्रस्तावित भारी-भरकम 750 वर्ग किलोमीटर का जमीन-अधिग्रहण, जिससे न जाने और कितने गांवों का अस्तित्व मिट जाने वाला है!)

प्रस्तावित रावघाट खदानों के लिए टाउनशिप कहां बने, इस बात को लेकर नारायणपुर और अंतागढ़ के व्यापारी वर्गों में मारामारी मची हुई है। इन स्वार्थी लोगों को इस बात की चिंता बिलकुल ही नहीं है कि इस क्षेत्र में खदान खुलने से कितने गांव उजड़ जाएंगे, कितने हजार आदिवासी विस्थपित हो जाएंगे, कितना जंगल कटेगा, कितनी नदियां प्रदूषित होंगी, विशिष्ट आदिवासी संस्कृति का किस हद तक विनाश होगा और कुल मिलाकर कितनी तबाही होगी। वे यही सोचकर सरकार के 'बस्तर विकास' के झूठे दावों में अपना सुर मिला रहे हैं कि खदानों से उनका धंधा बढ़ेगा।

इस रेल लाइन और खदान के पक्ष में सरकार अभी तक यह दलील देती आ रही थी कि चूंकि भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के लिए कच्चामाल की आपूर्ति करने वाली दल्ली राजहरा की खदानें खत्म होने जा रही हैं, इसलिए रावघाट में लोहा खोद निकालना जरूरी है। इसे बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा है कि अगर रावघाट में खदान शुरू नहीं होगी तो कच्चामाल के अभाव में बीएसपी बंद पड़ सकता है जिससे हजारों मजदूरों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाया गया कि रावघाट खदान के खिलाफ कोई अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेगा, तो उस पर फौरन ही 'विकास विरोधी' का ठप्पा लगाया जाता रहा है। सच तो यह है कि इस प्रचार की आड़ में सरकार और प्रशासन ने कई सच्चाइयों पर परदा डाल रखा है।

बीएसपी प्रबंधन की गलत नीतियों और खासकर अंधाधुंध मशीनीकरण के कारण ही दल्ली शहर आज लगभग उजाड़ की स्थिति में है। इस क्षेत्र के सभी नदी-नाले बुरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। दल्ली और उसके आसपास के कई गांवों के किसानों के खेतों में खदानों और सड़कों से निकली लाल मिट्टी भर जाने से खेती-किसानी बर्बाद हो चुकी है। अंधाधुंध मशीनीकरण के चलते ही दल्ली में जहां एक समय 16 हजार मजदूर हुआ करते थे, वहीं आज उनकी संख्या 1200 तक घट गई। फिलहाल रावघाट परियोजना का समर्थन करने वाले नारायणपुर, अंतागढ़ और जगदलपुर क्षेत्र के व्यापारी वर्ग और रायपुर में बैठे ठेकेदार क्या इस बात की गारंटी दे सकेंगे कि 20-25 सालों के बाद यह इलाका भी दल्ली जैसा नहीं होगा?

'कच्चा माल नहीं मिलेगा तो बीएसपी बंद हो सकता है' - यदि इस बात को लेकर सरकार वाकई चिंतित है, तो वह बैलाडीला से एनएमडीसी द्वारा जापान, चीन और कोरिया की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लोहा बेचना बंद क्यों नहीं करवाती? दरअसल रायपुर-भिलाई के कई स्पंज आयरन कारखाने लौह अयस्क की आपूर्ति न होने के कारण बंद पड़ चके हैं। उन्होंने सरकार से कई बार गुहार लगाई कि उन्हें बैलाडीला से माल उपलब्ध करवाया जाए और वहां से लोहा विदेशों में भेजना बंद किया जाए। क्या इससे यह साबित नहीं हो जाता है कि सरकार के लिए बड़े एवं विदेशी पूंजीपतियों के हित ही सर्वोपरि हैं? क्या बीएसपी के भविष्य को लेकर सरकार की 'चिंता' महज एक ढोंग नहीं है? क्या यह रावघाट खदान शुरू करने की राह में उठने वाले विरोध के मद्देनजर अपनाया जा रहा हथकण्डा नहीं है?

बीएसपी के भविष्य को लेकर या उसके सामने मौजूद खतरों को लेकर चिंतित तमाम मजदूरों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से हमारा आग्रह है कि वे यह पहचानें कि दरअसल बीएसपी को खतरा किन लोगों से है। 1960 के दशक में जब भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी तब उसमें सालाना 1.5 मिलियन टन का उत्पादन होता था और उसमें 95 हजार मजदूर काम करते थे। आज उत्पादन तीन गुना बढ़कर 4.5 मिलियन टन का हो गया, लेकिन मजदूरों की संख्या 37 हजार से भी कम हो गई। बीएसपी में ठेकेदारीकरण, मशीनीकरण और आंशिक निजीकरण की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। मजदूरों को मिलने वाली कई सुविधाओं को समाप्त किया गया है। नई भर्ती और अनुकम्पा नियुक्ति बंद हो चुकी हैं। 2012-13 तक इसका आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण कर उत्पादन को 7.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना है। इसका मतलब है और भी मजदूरों की छंटनी और भी 'सेवानिवृत्तियां' होंगी। और ऐसे भी चर्चे ये भी हैं कि भिलाई स्टील प्लांट को धीरे-धीरे टाटा, मित्तल या जिंदल को बेच दिया जाएगा। बाल्को का अनुभव हमारे सामने है। कुल मिलाकर, इस स्थिति के लिए सरकारों द्वारा लागू साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। इसलिए बीएसपी को बचाना है तो आप लोगों को सरकारों की मजदूर-विरोधी व पूंजीपति-परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। किसी दूसरे इलाके में खदानें खोलकर वहां के जल-जंगल-जमीन पर तबाही ढाने वाली साजिशों का कतई समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि विरोध करना है। आपके संघर्षों का समूची दण्डकारण्य जनता समर्थन करेगी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ़ के तमाम मजदूरों, किसानों और देश के तमाम जनवादपसंदों व देशभक्तों का आह्वान करती है कि वे रावघाट परियोजना को बंद करने की मांग करें; भिलाई स्टील प्लांट और अन्य उद्योगों में जारी मशीनीकरण और ठेकेदारीकरण के साथ-साथ सभी मजदूर-विरोधी नीतियों का विरोध करें; बैलाडीला से उच्च कोटि का लौह अयस्क औने-पौने दाम पर विदेशों में भेजना बंद करने की मांग करें; अपने जल-जंगल-जमीन पर अधिकार के लिए लड़ रहे दण्डकारण्यवासियों का समर्थन करें और उनके जायज संघर्षों का दमन के लिए की जा रही सेना की तैनाती का विरोध करें।

Gudsa Usendi

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)